RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 124
दि. 03.09.2025, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.
Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

संक्षिप्त समाचार

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार समारोह वर्ष 2025

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के स्वायत्त निकाय डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन ने आज नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेधावी पुरस्कार समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह समारोह अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने कक्षा 10वीं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस शुभ मंगलवार को अत्यंत आशाजनक पहल की शुरूआत की जा रही है। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि बिहार में माताओं और बहनों को जीविका निधि साख सहकारी संघ के माध्यम से एक नई सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल से गांवों में जीविका से जुड़ी महिलाओं को सुगमता से वित्तीय सहायता मिलेगी, जो उनके काम और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जीविका निधि प्रणाली पूरी तरह डिजिटल है, जिससे संबंधित काम के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी

और सब कुछ मोबाइल फोन के माध्यम से ही किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने जीविका निधि साख सहकारी संघ के शुभारंभ पर बिहार की माताओं और बहनों को बधाई देते हुए इस उल्लेखनीय पहल के लिए श्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की सराहना की।

श्री मोदी ने कहा कि सशक्त महिलाएं विकसित भारत का प्रमुख आधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके जीवन की कठिनाइयां कम करना आवश्यक है।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार माताओं, बहनों और बेटियों के जीवन को सुगम बनाने हेतु कई पहल कर रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि खुले में शौच बाध्यता से मुक्ति के लिए महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों पक्के घर बनाए गए हैं, और जिसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि ये घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हों। उन्होंने कहा कि जब एक महिला गृहस्वामिनी बनती है, तो उसकी बातों की अहमियत भी बढ़ जाती है।

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी, जानें- क्या होंगे फायदे

लखनऊ (जीएनएस)। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई। बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी, जिसमें कम्पनीज एक्ट-2013 के सेक्शन-8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जिसे नान-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा।

इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन तीन वर्ष के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है। इस निर्णय के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं को बेहतर अवसर देगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार और सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित करेगा।

क्यों जरूरी था निगम का गठन

प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे। लेकिन, लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थीं कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का नियमित अंशदान भी कई बार एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता था। इन अनियमितताओं को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह निगम गठित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण का प्रावधान

वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का भी अधिकार दिया जाएगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 हजार रुपये अंतिम संस्कार सहायता के रूप में दिए जाएंगे।

'आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि...', जापान और चीन दौरे का जिक्र कर ऐसा क्या बोले पीएम मोदी कि खूब लगे ठहाके

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन सोमवार (01 सितंबर, 2025) को जापान और चीन का दौरा करके भारत लौटे हैं। आज मंगलवार (02 सितंबर, 2025) को सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरूआत एक हल्की-फुल्की टिप्पणी से की। दरअसल, संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के दौरे का जिक्र करते हुए कहा, "कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा पूरी करके लौटा हूं।" इसके बाद लोग तालियां बजाने लगते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, "आप सब इसलिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि मैं वहां गया था या इसलिए कि मैं वापस आया हूं?"

'सेमीकंडक्टर के मिशन पर हो रहा काम'

पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधार महत्वपूर्ण खनिज हैं और देश ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा, "हम भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण पर काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत में बनी सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "सरकार नई डीएलआई (डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव) योजना को आकार देने जा रही है।"

'भारत ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया'

'मृत अर्थव्यवस्था' के कटाक्ष का परोक्ष रूप से खंडन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहली तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी, जो वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित चुनौतियों के बावजूद सभी उम्मीदों से अधिक है। मोदी ने कहा, "एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अनुमान और हर पूवार्नुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है।"

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कल प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों को एक ही परिसर में स्थापित किए जाने को लेकर दिशानिर्देश जारी करेंगे

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल) के सहयोग से कल (बुधवार, 3 सितंबर, 2025) नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को एक ही परिसर में स्थापित किए जाने को लेकर पर दिशानिर्देश जारी करेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दोनों विभागों के प्रतिनिधि और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे।

भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-IV मेघालय में प्रारंभ हुआ

(जीएनएस)।

भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-IV का 14वां संस्करण आज से मेघालय के उमरोई स्थित जॉइंट ट्रेनिंग नोड (जेटीएन) में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ प्रारंभ हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 1 से 14 सितंबर, 2025 तक किया जा रहा है। यह द्विपक्षीय अभ्यास दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य आदान-प्रदान कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच सहयोग, संयुक्त सहभागिता और आपसी समझ को विस्तार देना है। इससे पहले इस अभ्यास का 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिराप्राकन में आयोजित किया गया।

भारतीय सेना की टुकड़ी में 120 सैन्य कर्मी शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। वहीं, रॉयल थाई आर्मी की 53 कर्मियों वाली टुकड़ी का प्रतिनिधित्व प्रथम इन्फैंट्री बटालियन, 14वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है।

दोनों देशों के बीच होने वाला यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय श्क्क के अंतर्गत अर्ध-शहरी इलाकों में कंपनी स्तर के आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। दो सप्ताह के इस आयोजन में सामरिक अभ्यास, संयुक्त कार्य योजना, विशेष हथियार कौशल, शारीरिक क्षमता निर्माण और छापामार कार्रवाई शामिल हैं। यह अभ्यास 48 घंटे के प्रमाणीकरण अभ्यास के साथ समाप्त होगा, जिसमें यथार्थवादी परिचालन परिदृश्यों का अनुकरण किया जाएगा।

अभ्यास मैत्री भारत व थाईलैंड के बीच वर्ष 2006 में शुरू किया गया था और यह महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है। वर्तमान संस्करण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को पहले से अधिक सशक्त करता है और यह क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा के प्रति दोनों सेनाओं की साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

कपास खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुव्यवस्थित करने हेतु भारतीय कपास निगम के ऐप का शुभारंभ

केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद सुविधाजनक बनाने के लिए, वस्त्र मंत्रालय के भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा विकसित नए मोबाइल एप्लिकेशन, कपास किसान ऐप का आज शुभारंभ किया। नया मोबाइल ऐप किसानों को स्व-पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान स्थिति जानने में सहायक है। यह ऐप किसानों को भुगतान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा - जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक तेजी, पारदर्शिता और सुगमता आएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की

आगामी खेल महोत्सव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रविन्द्र भवन, भोपाल में अपने संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही क्षेत्र के किसान कल्याण के कार्यों, ग्रामीण विकास और अन्य विभिन्न कार्यों समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आगामी खेल महोत्सव की रूपरेखा, कार्यक्रमों और प्रबंधन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की। श्री शिवराज सिंह ने पदाधिकारियों से कहा कि, खेल महोत्सव केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और युवा ऊर्जा के प्रदर्शन का बड़ा मंच है। उन्होंने आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी को जिम्मेदारी के साथ योगदान देने का आह्वान किया। बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्यकर्ता या क्षेत्र का कोई भी नागरिक बीमार होता है तो उसका समुचित इलाज करवाना हमारा परम कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने स्वेच्छा अनुदान के माध्यम से अनेक जरूरतमंदों की मदद की। उन्होंने कहा कि आज भी यदि किसी को गंभीर बीमारी होती है और आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, तो वे व्यक्तिगत प्रयासों से संसाधन जुटाकर इलाज की व्यवस्था कराने का प्रयास करते हैं। जरूरत पड़ी तो हर संभव प्रयास करके इलाज कराया जाएगा। साथ ही श्री शिवराज सिंह ने

अपने संसदीय क्षेत्र स्थित सुकरवास गांव का एक वाकया सुनाते हुए कहा कि गांव का एक युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था और बहुत गरीब परिवार का था। तो गांव वालों ने उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपये से भी ज्यादा की राशि एकत्रित की। फिर मुझे खबर मिली तो मैं दिल्ली से सीधे अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर्स से चर्चा कर आयुष्मान कार्ड की मदद से उनका बेहतर इलाज हुआ।

स्थायित्व संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारत सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले जी-20 देशों में शामिल: श्री पीयूष गोयल

भारत अब विश्व स्तर पर सबसे किफायती दरों पर चौबीसों घंटे अक्षय ऊर्जा प्रदान करता है: श्री पीयूष गोयल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इम्पेक्ट' मंत्र हमारी प्रतिबद्धता है: श्री गोयल

भारत एफटीए के माध्यम से वैश्विक साझेदारी का विस्तार कर रहा है, द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है: श्री पीयूष गोयल

(जीएनएस)।

भारत स्थायित्व संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जी20 देशों में से एक है। यह बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के 20वें वैश्विक स्थायित्व शिखर सम्मेलन में कही।

पर्यावरण के क्षेत्र में भारत की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीओपी-21 को सफल बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, "सीओपी-21 को सफल बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना, अल्प विकसित देशों के स्थायित्व संबंधी प्रयासों में योगदान देने के लिए विकसित देशों के साथ उनके सहयोग के बिना, शायद सीओपी-21 का विलय नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे वैश्विक दक्षिण को एक साथ लाकर यह संदेश दिया कि यह दुनिया के प्रत्येक देश की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।"

श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, 2014 से अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों को पांच गुना बढ़ा रहा है और "एक राष्ट्र, एक ग्रिड" के सिद्धांत के तहत आपस में जुड़े एक राष्ट्रीय ग्रिड का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है।

बिजली क्षेत्र में उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, श्री गोयल ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों को निर्धारित समय से काफी पहले प्राप्त कर रहा है, और 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहले ही स्थापित हो चुकी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचना है, जो मेक इन इंडिया उत्पादों, आत्मनिर्भर विनिर्माण और तीव्र नवाचार द्वारा संचालित होगा। उन्होंने कहा कि भारत में अब 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति के लिए लगभग 4.60 रुपये से 5.00 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर पर अक्षय ऊर्जा उपलब्ध है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती दर है। उन्होंने यह भी कहा कि कोयला और अक्षय ऊर्जा को एक साथ अपनाने में कोई विरोधाभास नहीं है, और पारदर्शी बोली की प्रक्रियाओं ने सौर ऊर्जा की कीमत 7-8 रुपये से घटाकर 2.41 रुपये कर दी है।

श्री रजनीश कुमार गोयल ने पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर का कार्यभार ग्रहण किया

मुंबई,

श्री रजनीश कुमार गोयल भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरी सेवा (IRSEE) के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी ने पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले आप मध्य रेल में मुख्य विद्युत सेवा इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे।

श्री गोयल अत्यधिक कुशल हैं तथा आपको भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव प्राप्त है। भारतीय रेल में ओपन एक्सेस के अग्रदूत के रूप में आपने इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 10 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। श्री गोयल ने मध्य रेल के मुंबई मंडल के मंडल रेल प्रबंधक का

महत्वपूर्ण दायित्व संभाला है, जो भारतीय रेल के सबसे बड़े और व्यस्ततम मंडलों में से एक है। मध्य रेल के मुंबई मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आपको प्लेटफॉर्मों पर भीड़भाड़ कम करने, पटरियों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अग्रणी कार्य करने और पटरियों पर पानी भर जाने के बावजूद उपनगरीय ट्रेन परिचालन को संभव बनाने सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवपरिवर्तनों के लिए याद किया जाता है।

आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक (ऑनर्स) पूरा किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से आपने "पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन और ड्राइव्स" में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।

उधना स्टेशन पर कुछ ट्रेनों के ठहराव 3 सितंबर, 2025 से बहाल

मुंबई,

उधना स्टेशन का पूर्ण रूप से कायाकल्प हो रहा है और इसे विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उधना स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर (फेज-क्क) पुनर्विकास का कार्य पूरा हो चुका है। इसी के मद्देनजर उधना स्टेशन पर कुछ ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिसे 3 सितंबर, 2025 से पुनः बहाल किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उधना स्टेशन पर चल रहे प्लेटफॉर्म संख्या 1 के पुनर्विकास कार्य का दूसरा चरण पूरा हो गया है। इस कार्य हेतु लिये गये ब्लॉक के कारण उधना स्टेशन पर कुछ डाउन ट्रेनों के ठहराव अस्थायी रूप से हटा दिये गये थे, जिन्हें 3 सितंबर, 2025 से बहाल किया जा रहा है। इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 19033 वलसाड-अहमदाबाद गुजरात क्वीन एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 59049 वलसाड-वडोदरा पैसेंजर
3. ट्रेन संख्या 19101 विरार-भरूच एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 19015 दादर-पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस
5. ट्रेन संख्या 69151 वलसाड-सूरत मेमू
6. ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली-वटवा एक्सप्रेस
7. ट्रेन संख्या 12921 मुंबई-सूरत फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस
8. ट्रेन संख्या 69141 संजान-सूरत मेमू

महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद मंडल के दो कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया

रेलवे के संचालन में संरक्षा सर्वोपरि होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी की सजगता एवं सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने अहमदाबाद मंडल के दो रेल कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार जून एवं जुलाई 2025 के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए सतर्कता दिखाने और संभावित दुर्घटनाओं को समय रहते टालने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदान किए गए।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी (1) श्री रामकेश मीना, पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के 'डीसा' में सीनियर ट्रैकमेंटेनर के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 28 जुलाई 2025 को ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान, उन्होंने अपने नियमित पेट्रोलिंग कार्य के दौरान व्हील से चिंगारी निकलते हुए देखा।

संरक्षा की दृष्टि से बड़ी समस्या है, जो रेल की पटरी पर अधिक घर्षण या ब्रेक लगने से उत्पन्न होता है और अगर समय पर इसका समाधान नहीं किया जाए, तो यह बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। श्री मीना ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिना समय गंवाए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जिससे संरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई की जा सकी।

उनकी यह तत्परता, विवेकशीलता और जिम्मेदारी का परिचायक है, जिसकी बदौलत एक संभावित रेल दुर्घटना को रोका जा सका। श्री मीना का कार्य न केवल सराहनीय है, बल्कि यह अन्य फील्ड कर्मचारियों के लिए एक आदर्श उदाहरण भी है।

(2) श्री अरुण कुमार, पश्चिम रेलवे के कोचिंग डिपो कांकरिया में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 26 जुलाई 2025 को, जब वे एक्सल बॉक्स बेयरिंग की नियमित तापमान निगरानी का कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने कोच संख्या 233941 के एक्सल संख्या 03 पर असामान्य तापमान वृद्धि दर्ज की। एक्सल बॉक्स का अत्यधिक गर्म होना या 'हॉट एक्सल' की स्थिति रेल परिचालन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। श्री अरुण कुमार ने इस संभावित खतरे को भांपते हुए बिना किसी देरी के ट्रेन के प्रभारी को इसकी जानकारी दी। उनकी त्वरित सूचना पर आवश्यक सावधानियाँ बरती गईं और गाड़ी को सुरक्षित रूप से परिचालित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए। वापसी यात्रा के दौरान भी उन्होंने लगातार उस कोच के तापमान की निगरानी की। उनकी निरंतर निगरानी और सजगता ने एक्सल को अधिक गर्म होने से रोका और एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया।

महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने दोनों कर्मचारियों की सतर्कता और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि"इन कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन न केवल ईमानदारी और लगन से किया, बल्कि रेलवे संरक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का भी परिचय दिया। ब्रेक बाइंडिंग, हॉट एक्सल जैसे संभावित जोखिमों को समय रहते पहचानकर उन्होंने हजारों यात्रियों की जान-माल की रक्षा सुनिश्चित की है। यह समर्पण और सजगता समस्त रेलवे कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा है।"

पश्चिम रेलवे को अपने ऐसे कर्मचारियों पर गर्व है, जो विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी के साथ कार्य करते हैं और रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना है, बल्कि यह पश्चिम रेलवे की उस संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करता है, जहाँ संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

पश्चिम रेलवे वटवा और रक्सौल के बीच चलाएगी त्योहार स्पेशल ट्रेन

मुंबई, 02 सितंबर, 2025

ट्रेन संख्या 05560/05559 उधना-रक्सौल के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष तौर पर त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा माँग को पूरा करने के उद्देश्य से वटवा और रक्सौल के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, उधना एवं रक्सौल के बीच विशेष किराए पर चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन के फेरों को मौजूदा समय, ठहराव और संरचना के अनुसार विस्तारित किया आगे बढ़ाया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 05562/05561 वटवा - रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल [32 फेरे]

ट्रेन संख्या 05562 वटवा - रक्सौल स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को 23:30 बजे वटवा से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन शुक्रवार को 16:00 बजे रक्सौल पहुँचेगी। यह ट्रेन 17 सितंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05561

रक्सौल - वटवा स्पेशल ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 11:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20:00 बजे वटवा पहुँचेगी। यह ट्रेन 16 सितंबर से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, संत हिरदाराम नगर, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुरवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 05560/05559 उधना-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल के फेरे विस्तारित [26 फेरे]

ट्रेन संख्या 05560 उधना-रक्सौल स्पेशल को 05 अक्टूबर से 28 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल को 04 अक्टूबर से 27 दिसंबर, 2025 तक मौजूदा समय, ठहराव और संरचना के अनुसार विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 05562 की बुकिंग एवं ट्रेन संख्या 05560 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 03 सितम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस-अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष तौर पर त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस और अजमेर के बीच विशेष किराये पर चल रही स्पेशल ट्रेन के फेरों को मौजूदा समय, ठहराव और संरचना के अनुसार विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 09622/09621 बांद्रा टर्मिनस - अजमेर (साप्ताहिक) स्पेशल [18 फेरे]

ट्रेन संख्या 09622 बांद्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक सोमवार को बांद्रा टर्मिनस से 09:35 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 08:50 बजे अजमेर पहुँचती है। इस ट्रेन के फेरों को 06 अक्टूबर से 1 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09621 अजमेर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार को अजमेर से 06:35 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 04:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचती है। इस ट्रेन के फेरों को 05 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, विक्रमगढ़ आलोट, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर और किशनगढ़ स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास के डिब्बे हैं।

ट्रेन संख्या 09622 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 04 सितम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अयोध्या में सीएम योगीः बिमलेंद्र मोहन को देंगे श्रद्धांजलि, पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे

अयोध्या (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एकदिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे। इस दौरान श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के त्रयोदशाह संस्कार के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

अयोध्या राज परिवार के दिवंगत मुखिया और श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के त्रयोदशाह संस्कार के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद राज सदन जाएंगे।

डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीएम योगी का हेलीकाप्टर बुधवार शाम छह बजे रामकथा पार्क के हेलीपैड पर उतरेगा। यहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमंत लला को श्रद्धा निवेदित करने के बाद श्रीराम जन्मभूमि पहुंचेंगे। यहां पर रामलला और राजा राम के दरबार में मत्था टेकने के बाद राज सदन पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री की ओर से राजसदन में अयोध्या राज परिवार के दिवंगत मुखिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और कला जगत की नामचीन हस्तियों के भी आने की संभावना है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी आ सकते हैं। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य पदाधिकारी व ट्रस्टी मौजूद रहेंगे।

सीएम समेत कई अन्य विशिष्टजनों के आने के चलते डीएम और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर की देखरेख में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मंगलवार को राजसदन का भ्रमण कर सुरक्षा और पार्किंग के इंतजामों का खाका तैयार किया। एडीएम सिटी योगानंद पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट राजेश मिश्र व एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी समेत कई अन्य अफसर देर रात तक राजसदन में मौजूद रहकर तैयारियों को अंतिम रूप देते रहे।

गृहमंत्री अमित शाह ने भेजी शोक संवेदना

अयोध्या राज परिवार के दिवंगत मुखिया और श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शोक संवेदना भेजी गई है। गृह मंत्री ने पत्र के माध्यम से बिमलेंद्र मोहन के निधन को अपूर्णनीय क्षति बताया है।

4 से 6 सितंबर तक भारत मंडपम में इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का आयोजन, सीईओ गोलमेज बैठकें, फायरसाइड चैट और राज्य-केंद्रित सत्र शामिल होंगे

भारत की मेडटेक क्षेत्र की ताकत और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए 4 से 6 सितंबर तक भारत मंडपम में इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का आयोजन

मेडटेक एक्सपो 2025 में एमएसएमई, स्टार्ट-अप, अनुसंधान मंडप शामिल, 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ सरकारी पहल

मेडटेक विनिर्माण और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री, उद्योग जगत के दिग्गज और वैश्विक विशेषज्ञ इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 में भाग लेंगे

(जीएनएस)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएमडी) और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से औषधि विभाग, भारत स्वास्थ्य 2025 पहल के एक भाग के रूप में, 4 से 6 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में दूसरा इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 आयोजित करेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री नितिन कुमार यादव, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के अध्यक्ष श्री पी. कृष्णमूर्ति, औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी और औषधि विभाग के संयुक्त सचिव श्री आर. पी. सिंह इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल होंगे।

भारत मेडटेक एक्सपो चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरण क्षेत्र में भारत की क्षमताओं और विकास को उजागर करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। 2025 का आयोजन एक बार फिर नीति निमार्ताओं, वैश्विक व्यापार जगत के दिग्गजों, नवप्रवर्तकों, निवेशकों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाएगा, जिससे भारत की स्थिति समाधान केन्द्रित, किंतु किफायती, मेडटेक समाधानों के केंद्र के रूप में मजबूत होगी।

'भारतः वैश्विक मेडटेक विनिर्माण केंद्र, समाधान आधारित इंजीनियरिंग किंतु किफायती' विषय पर आधारित तीन दिवसीय एक्सपो में एमएसएमई, स्टार्ट-अप, अनुसंधान संस्थान, भविष्य के नवाचार मंडप, राज्य प्रदर्शनियां और सरकारी पहलों को प्रदर्शित करने वाली एक विस्तृत प्रदर्शनी होगी।

इस कॉन्क्लेव में विषयगत सम्मेलन, सीईओ गोलमेज बैठकें, फायरसाइड चैट और राज्य-केंद्रित सत्र शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय और राज्यों के मंत्री भी भाग लेंगे। अनुभव क्षेत्र और नेटवर्किंग के अवसर जैसे बी2बी बैठकें, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें और नियामक ओपन हाउस, मेड-टेक मूल्य श्रृंखला में सहयोग को और भी अधिक बढ़ावा देंगे।

अन्य प्रमुख वक्ताओं में उत्तर प्रदेश के वाईईआईडीए, मेडिकल डिवाइस पार्क के सीईओ श्री राकेश कुमार सिंह, औषधि विभाग के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री अवधेश चौधरी, उप औषधि नियंत्रक (भारत), सीडीएससीओ आईवीडी प्रभाग श्री प्रमोद मेश्राम आदि शामिल होंगे।

आगामी आयोजन के बारे में, ईपीसीएमडी के कार्यकारी निदेशक श्री प्रवीण कुमार मित्तल ने कहा, "भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार आकार तक बढ़ गया है और 2030 तक इसके 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 800 से अधिक मेडटेक स्टार्ट-अप, मजबूत अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं और तेजी से बढ़ते विनिर्माण आधार के साथ, हम भारत को न केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में, बल्कि एक वैश्विक नवाचार और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 इस विकास गाथा को प्रदर्शित करने और ऐसे सहयोगों को सक्षम करने में उत्प्रेरक का काम करेगा जो भारत और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में बदलाव ला सकते हैं।"

इस आयोजन में 30 से अधिक देशों के 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे, जो वैश्विक हितधारकों को भारत के तेजी से बढ़ते मेडटेक इको-सिस्टम में साझेदारी और निवेश की संभावनाओं को तलाशने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।

एक्सपो में विशेष मंडपों में 350 से अधिक प्रदर्शक एक साथ आएंगे और सम्मेलन सत्रों का आयोजन किया जाएगा, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक मेडटेक क्षेत्र में भारत के विजन 2047 को आगे बढ़ाया जा सके।

इंडिया मेडटेक एक्सपो की मुख्य विशेषताएंः

भारत की सबसे बड़ी चिकित्सा उपकरण प्रदर्शनी जिसमें 500 से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करेंगी।

वैश्विक और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए संघ और राज्य एजेंसियों द्वारा पांच-वर्षीय मांग प्रस्तुतियां।

भारतीय और वैश्विक कंपनियों, स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, अनुसंधान संस्थानों और सरकारी मंडपों की मजबूत भागीदारी।

आसियान, अफ्रीका, सीआईएस, मध्य पूर्व और ओशिनिया के 30 से अधिक देशों से 150 से अधिक प्रतिनिधि।

निमार्ताओं, नियामक निकायों, राज्य सरकारों और मंत्रालयों सहित 350 से अधिक प्रदर्शक।

आईआईटी, आईआईएससी, एम्स, आईसीएमआर, नीति आयोग और विश्व बैंक जैसे प्रमुख संस्थानों और थिंक टैंकों के विशेषज्ञ।

छह विशिष्ट मंडपः एमएसएमई, भविष्य, अनुसंधान एवं विकास, सरकार, राज्य और स्टार्ट-अप।

पांच राज्य विनिर्माण और निवेश के अवसर प्रदर्शित कर रहे हैं।

रसायन निर्यातकों के लिए बड़ी राहतः निर्यात देयता अवधि को वर्तमान 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने की गई

सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण के तहत डीसीपीसी द्वारा अधिसूचित क्यूसीओ उत्पादों के लिए निर्यात देयता अवधि को वर्तमान 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया है

(जीएनएस)।

रसायन उद्योग ने रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) के अनुरोध पर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा दिनांक 28.05.2025 की अधिसूचना संख्या 28 के तहत जारी एक महत्वपूर्ण निर्णय का स्वागत किया है। इस निर्णय के अंतर्गत, उन उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकरण के अंतर्गत निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ा दी गई है जिन्हें डीसीपीसी द्वारा अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। निर्यात दायित्व की अवधि अब 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई है, जिससे उद्योग को काफी सुविधा और समर्थन प्राप्त होगा।

यह पहल वस्त्र मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत अधिसूचित क्यूसीओ के लिए किए गए इसी तरह के समायोजन के बाद आई है, जहाँ समय सीमा को बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया था। यह पहल पूरे भारत में रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स के निर्यातकों को महत्वपूर्ण सहायता और मजबूती प्रदान करती है। यह कदम व्यापार को सुगम बनाने और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत, आयातक निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क-मुक्त कच्चा माल आयात कर सकते हैं और ये कच्चे माल गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अधीन नहीं होते, जिससे निर्यात गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित होती है। इनमें से बड़ी संख्या में कच्चे माल रासायनिक क्षेत्र को दिए गए हैं, जो इस नीतिगत बदलाव के महत्व को दशार्ता है।

भारत सरकार एक विशिष्ट रणनीति के माध्यम से रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का निर्यात 46.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रभावशाली स्तर पर पहुँच गया, जो देश के कुल निर्यात मूल्य का 10.6 प्रतिशत है, जिससे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और भी पुष्ट होती है।

यह कदम कच्चे माल की लागत से उत्पन्न वित्तीय दबाव को कम करने, कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भारतीय रासायनिक उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग और डीजीएफटी की पहल एक दूरदर्शी और रणनीतिक दृष्टिकोण को दशार्ती है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

अपराधों में पकड़े जाने वाले विदेशियों के लिए भारत का दरवाजा बंद

केंद्रिय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि हाल ही में लागू किए गए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम : 2025 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विदेशियों के आवागमन को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से समर्पित निरुद्ध केंद्र या हिरासत शिविर स्थापित करेगा, जब तक कि उन्हें निर्वासित कर नहीं दिया जाता। लगे हाथ गृह मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि विदेशियों पर यदि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, जासूसी, बलात्कार और हत्या, आतंकी गतिविधियों बाल तस्करी या किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने का आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति देने से मना किया जा सकता है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी विरोधी जिसके पास भारत में रोजगार के लिए वैध वीजा हो, बिना नागरिक प्राधिकरण की अनुमति के बिजली या जल आपूर्ति से जुड़े निजी क्षेत्र के उपक्रमों या पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत किसी संस्था में रोजगार स्वीकार नहीं कर सकता। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस आदेश में यह भी कहा गया है कि मादक पदार्थों और मनः प्रभावी पदार्थों की तस्करी, बाल तस्करी सहित मानव तस्करी, नकली यात्रा दस्तावेजों क्रिप्टोकरेंसी सहित मुद्रा में धोखाधड़ी, साइबर अपराध, बाल दुर्व्यवहार या ऐसे अपराधों में संलिप्त पाया जाना, वित्त शोधन अथवा हवाला संबंधी आर्थिक अपराधों में पकड़े जाने वाले विदेशियों के लिए भारत का दरवाजा बंद अपराधों का जिस तरह वगाकरण करके विदेशियों को जिस तरह देश से बाहर करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किया गया है, वह निति रूप से इस बात का परिचायक है कि क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सतर्क होना स्वाभाविक है।

दरअसल संगठित अपराध के ठेकेदारों के लिए अवैध घुसपैठिए सहजतापूर्वक प्राप्त मानव संसाधन होते हैं। इसलिए अपराध के विभिन्न क्षेत्रों में ये विदेशी नागरिक सक्रिय रहते हैं। दुःखद एवं हैरानी की बात तो यह है कि इन अवैध विदेशी घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड देकर सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है।

मजे की बात तो यह है कि जब ये शातिर अपराधी किसी राजनीतिक पाटा का झंडा उठा लेते हैं तो इनकी सुरक्षा में पूरी पाटा खड़ी हो जाती है। सच तो यह है कि इन अपराधियों के खिलाफ यदि पुलिस, जांच एजेंसियां अथवा खुफिया तंत्र कोई कार्रवाई करती है तो राजनीतिक दल संबंधित एजेंसियों को लोकतंत्र का हत्यारा साबित करने में जुट जाते हैं।

बहरहाल यह तो सच है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश में कानून पहले से ही है और उसके सन्नियम प्रभावी भी हैं किन्तु दुर्भाग्य यह है उनका उपयोग करने वाली एजेंसियां या तो सही तरीके से सतर्कतापूर्वक कार्रवाई करती नहीं या उन्हें करने ही नहीं दिया जाता। नागरिकता कानून के तहत केंद्रीय कानून प्रभारी है, जो जरूरतमंद विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के लिए पर्याप्त है किन्तु अपराधी प्रवृत्ति के घुसपैठिए कानूनी तरीके से नागरिकता चाहते ही नहीं। लब्बोलुआब यह है कि यदि केंद्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियां मिल कर अवैध घुसपैठियों को पकड़ना तेज कर दें तो इनका आतंक कम हो सकता है। किन्तु सच यह भी है कि इन घुसपैठियों की मदद लेने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी राज्य सरकारों पर मजबूत पकड़ है। ये खुद अपने आप अपराध की दुकान नहीं चलाते बल्कि ये हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पहले उन लोगों पर कार्रवाई हो जो इन घुसपैठियों से तमाम तरीके से अपराध करवाते हैं।

'स्वागत' ऑनलाइन कार्यक्रम : जनता और शासन के बीच सेतु को और अधिक मजबूत कर रही है गुजरात सरकार

'स्वागत' कार्यक्रम के जरिए महुवा के भरतभाई की वर्षों पुरानी भूमि स्वामित्व की समस्या हल हुई

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गत 4 वर्षों में 'स्वागत' के माध्यम से 2,39,934 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2003 में शुरू किया था स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम

गांधीनगर, 02 सितंबर : गुजरात सरकार पिछले दो दशकों में जनता और शासन के बीच सेतु को और अधिक मजबूत बनाने की विभिन्न पहलों को लागू करने में अग्रणी रही है। सुशासन को प्रोत्साहित करने वाली ऐसी ही एक पहल है- 'स्वागत' यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्ष 2003 में जब दुनिया डिजिटल क्रांति के लिए तैयार हो रही थी, तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आम जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को पाटने के लिए टेक्नोलॉजी में निहित क्षमता को पहचाना और इस तरह उन्होंने 'स्वागत' कार्यक्रम की शुरूआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के आम नागरिक अपनी शिकायतों और समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि 'स्वागत' कार्यक्रम शुरू होने के बाद से अब तक राज्य, जिला, तहसील और ग्रामीण स्तर पर नागरिकों की ओर से कुल 15,84,535 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 15,79,002 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है।

'स्वागत' : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गत 4 वर्षों में 2,39,934 शिकायतों का हुआ समाधान

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल आज सफलतापूर्वक 'स्वागत' कार्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं। उनके मजबूत नेतृत्व में 'स्वागत' कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं जनता की शिकायतों को सुनते हैं और उसकी समीक्षा कर उनका समाधान करते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में कुल 2,39,934 शिकायतों और समस्याओं का निवारण किया गया है।

भावनगर जिले के महुवा शहर निवासी भरतभाई काबाभाई खोडीफाड की समस्या यह थी कि उन्हें अपने ही भूखंड का आधिकारिक तौर पर स्वामित्व नहीं मिला था। महुवा नगर पालिका ने गरीब लोगों को भूखंड आवंटित करने के लिए भरतभाई के दादा की 9 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इस भूमि में से उन्हें जो रिहायशी भूखंड मिलना था, उसका कब्जा नगर पालिका ने उन्हें नहीं सौंपा था। नगर पालिका ने उन्हें इस भूमि को रिहायशी उद्देश्य के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव वर्ष 1967 में किया था। हालांकि, उनके पूर्वजों की अनभिज्ञता के कारण इस भूमि पर बने मकान का दस्तावेज नहीं बन पाया था। उन्होंने जब दस्तावेज तैयार करने के लिए नगर पालिका से अनुमति मांगी, तो उन्हें फिर से विभाग से स्वीकृति लेने को कहा गया। इसके बाद भरतभाई ने मकान को अपने नाम पर कराने के लिए तहसील और जिला 'स्वागत' में गुहार लगाई, जहां हल नहीं निकलने पर अंततः उन्होंने राज्य स्तरीय 'स्वागत' में शिकायत की।

भरतभाई कहते हैं, ह्लमुख्यमंत्री ने मित्रवत भाव से मेरी शिकायत सुनी और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर संबंधित अधिकारियों को भूमि का दस्तावेज तैयार करने के निर्देश दिए। इस प्रकार, मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के कारण मेरे वर्षों पुराने मुद्दे का समाधान हुआ और मेरे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जिस ऋण की आवश्यकता थी, उसकी प्रक्रिया हम शुरू कर सके ह्व

कैसे काम करता है स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम

उल्लेखनीय है कि स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य 'स्वागत', जिला 'स्वागत', तहसील 'स्वागत' और ग्राम 'स्वागत' कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जनता की गुहार सुनते हैं। जिला स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में नागरिकों की शिकायतें जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। वहीं, तहसील 'स्वागत' कार्यक्रम में नागरिक प्रांत अधिकारी और उनके समकक्ष प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतें रखते हैं। ग्राम 'स्वागत' कार्यक्रम के तहत नागरिकों को हर महीने की 1 से 10 तारीख के दौरान अपने आवेदन पटवारी या मंत्री को देने होते हैं। इन आवेदनों को बाद में तहसील 'स्वागत' में शामिल किया जाता है और उसके बाद उनका निपटारा किया जाता है।

इसके अलावा, राज्य के नागरिक अपनी शिकायतें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर या डाक के माध्यम से भी मान. मुख्यमंत्री के कार्यालय को भेज सकते हैं। इन आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों और संबंधित जिले को भेजा जाता है और लोगों की समस्याओं के संदर्भ में उचित कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही, वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री कार्यालय ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल- 'डब्ल्यूटीसी' (राइट टू सीएमओ-सीएमओ को लिखें) भी शुरू किया है। इसके अंतर्गत नागरिक अपनी शिकायतें इस पोर्टल के जरिए सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय को भेज सकते हैं। गुजरात सरकार राज्य के नागरिकों की समस्याओं को दूर कर उनके लिए 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जीवन जीने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।

31 अगस्त, 2025 तक 95,658 लोग वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम देखने पहुंचे

मेहसाणा में 9 और 10 अक्टूबर को आयोजित होने वाली 'वीजीआरसी' के दौरान आकर्षण का केंद्र बनेगा वडनगर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजिम

उत्तर गुजरात की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में झलकेगी भारत की समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत

गांधीनगर, (जीएनएस)। 2500 से अधिक वर्षों से निरंतर जीवंत वडनगर शहर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनमोल खजाना है। इस ऐतिहासिक शहर की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम-पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का निर्माण किया गया है।

इस संग्रहालय का उद्घाटन 16 जनवरी, 2025 को किया गया था और इसे 1 फरवरी से आगंतुकों के लिए खोल दिया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार, वडनगर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय को देखने के लिए 31 अगस्त, 2025 तक पूरे भारत से कुल 95,658 लोग पहुंच चुके हैं।

आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम को देखने के लिए पहुंचे आगंतुकों का यह आंकड़ा सांस्कृतिक पर्यटन के लिए एक दृष्टांत है। इन आगंतुकों में बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल हैं, जो दशार्ता है कि म्यूजियम हरेक व्यक्ति के लिए सुलभ है। इतना ही नहीं, यह स्थान शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी लोकप्रिय बनता जा रहा है।

वडनगर की 2500 वर्ष पुरानी विरासत का प्रतिबिंब है यह म्यूजियम

यह म्यूजियम व्यापक खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियों के माध्यम से वडनगर की 2500 वर्ष से अधिक पुरानी विरासत का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। 13,525 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस म्यूजियम में कला, स्थापत्य, व्यापार, शहरी नियोजन और भाषा आदि को प्रदर्शित करने वाली 9 थीमैटिक गैलरियां हैं। 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले उत्खनन स्थल पर पुरातात्विक अवशेषों को 16 से 18 मीटर की गहराई पर देखा जा सकता है। आगंतुकों को वडनगर के पुरातात्विक उत्खनन से मिले अवशेषों का अनुभव प्रदान करने के लिए एक स्थायी शेड बनाया गया है और अन्य पर्यटन सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

इस म्यूजियम में मिट्टी के बर्तन, शंख निर्माण, सिक्के, आभूषण, हथियार एवं औजार, शिल्प, खेल सामग्री तथा खाद्यान्न एवं कंकाल के अवशेषों जैसी जैविक सामग्री सहित 5000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ऑडियो-विजुअल फिल्मों और प्रदर्शनियों के आकर्षण वाला यह आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक विशेष सौगात है।

वीजीआरसी में आकर्षण का केंद्र बनेगा वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम

उल्लेखनीय है कि आगामी 9 और 10 अक्टूबर, 2025 को मेहसाणा में उत्तर गुजरात के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का आयोजन होने जा रहा है। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंस म्यूजियम आकर्षण का केंद्र बनेगा, जो क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को उजागर करेगा। जब वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में भारत की समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत प्रदर्शित होगी, तब गुजरात पर्यटन के सराहनीय कार्य भी लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे।

1,546 एनसीसी कैडेट दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में बारह दिनों के थल सैनिक शिविर में भाग लेने के लिए तैयार

(जीएनएस)।

देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों से 867 लड़के और 679 लड़कियों सहित कुल 1,546 कैडेट दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में बारह दिवसीय थल सैनिक शिविर में भाग लेंगे। अपर महानिदेशक (ए) एयर वाइस मार्शल पीवीएस नारायण 02 सितंबर, 2025 को इसका उद्घाटन करेंगे। शिविर में भाग लेने वाले कैडेट विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेंगे, जिनमें अवरोध प्रशिक्षण, मानचित्र पठन और अन्य संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इस पहल से उन्हें समृद्ध अनुभव प्राप्त होगा, जिसमें शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक तीक्ष्णता और टीम वर्क पर जोर दिया जाएगा।

थल सैनिक शिविर का उद्देश्य कैडेटों को सेना प्रशिक्षण के प्रमुख पहलुओं से अवगत कराना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना और अनुशासन, नेतृत्व एवं राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। यह शिविर सेना विंग के कैडेटों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर के शिविर के रूप में व्यापक प्रशिक्षण एवं चरित्र विकास पर केंद्रित है।

अपर महानिदेशक ने एनसीसी द्वारा देश के युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अनूठे अवसरों का उल्लेख किया, जो उनके रोमांच, अनुशासन और सम्मान से भरा जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि एनसीसी सभी कैडेटों में नेतृत्व व सौहार्द की भावना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें जीवन की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए तैयार करती है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 16 से 31 अगस्त 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया

(जीएनएस)।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 16 से 31 अगस्त 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा सफलतापूर्वक मनाया। यह मिशन पूरे देश में सफाई, स्वच्छता और स्थिरता को प्रोत्साहन देता है। दो सप्ताह का यह अभियान भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के कैलेंडर के अनुसार चलाया गया। इस गतिविधि ने स्वच्छता को एक साझा कर्तव्य बनाने और एक स्थायी कार्य वातावरण बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दशार्या।

इस आयोजन की शुरूआत 18 अगस्त 2025 को भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता पर शपथ ग्रहण समारोह के साथ हुई। भारी उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

भारी उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को 'स्वच्छता शपथ' दिलाते हुए।

पूरे पखवाड़े के दौरान, मंत्रालय परिसर में स्वच्छता और स्थिरता को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें शामिल हैं:

उद्योग भवन के सभी कमरों, सीढ़ियों, गलियारों और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान।

कार्यस्थलों को खाली करने के लिए अनुपयोगी फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य अप्रचलित वस्तुओं को हटाना।

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए जागरूकता अभियान।

'स्वच्छ भारत अभियान' विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

मंत्रालय के गलियारों में स्वच्छता बनाए रखना।

29 अगस्त, 2025 को स्वच्छता पखवाड़ा के एक भाग के रूप में उद्योग भवन परिसर के अंदर स्वच्छता बनाए रखने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री विजय मित्तल ने मंत्रालय के परिसर को स्वच्छ रखने में उनकी अटूट सेवा और उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के सम्मान में मंत्रालय के कर्मचारियों को उपहार वस्तुएं भेंट करके सम्मानित किया।

भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री विजय मित्तल, मंत्रालय के एक कार्यकर्ता को सम्मानित करते हुए

स्वच्छता पखवाड़ा (16-31 अगस्त, 2025) के अंतर्गत, भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने स्वच्छता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी इकाइयों में कई पहल कीं। 18 अगस्त, 2025 को बीएचईएल की रानीपेट, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, भोपाल और दिल्ली इकाइयों में कार्यकारी निदेशकों द्वारा जागरूकता बैनर प्रदर्शित किए गए और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया

वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी: भारत में डिजाइन, भारत में निर्मित, दुनिया द्वारा विश्वसनीय: प्रधानमंत्री

चिप डिजिटल हीरे हैं: प्रधानमंत्री

कागजी कार्रवाई जितनी कम होगी, वेफर का कार्य उतनी ही शीघ्रता से शुरू हो सकता है: प्रधानमंत्री

भारत की सबसे छोटी चिप बहुत जल्द दुनिया को सबसे बड़े बदलाव की ओर ले जाएगी: प्रधानमंत्री

वह दिन दूर नहीं जब भारत में डिजाइन किए गए, भारत में निर्मित को दुनिया द्वारा विश्वसनीय कहा जाएगा : प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित 'सेमीकॉन इंडिया-2025' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश-विदेश के सेमीकंडक्टर उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उनके सहयोगियों की उपस्थिति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विभिन्न देशों से आए विशिष्ट अतिथियों, स्टार्ट-अप से जुड़े उद्यमियों और देश भर के विभिन्न राज्यों से आए युवा छात्रों का स्वागत किया।

श्री मोदी ने कहा कि वे कल रात ही जापान और चीन की अपनी यात्रा से लौटे हैं और आज आकांक्षाओं और आत्मविश्वास से परिपूर्ण यशोभूमि के इस परिसर में दर्शकों के बीच उपस्थित हैं। हमेशा से स्वाभाविक और सर्वविदित प्रौद्योगिकी के प्रति अपने जुनून का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में अपनी जापान यात्रा के दौरान, उन्हें जापानी प्रधानमंत्री श्री शिगेरु इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन कारखाने का दौरा करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि उस कंपनी के सीईओ आज दर्शकों के बीच उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के प्रति उनका झुकाव उन्हें बार-बार ऐसे लोगों के बीच लाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दर्शकों के बीच उपस्थित होकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

दुनिया भर के 40 से 50 देशों के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों की उपस्थिति को देखते हुए, श्री मोदी ने कहा कि भारत की नवाचार और युवा शक्ति भी इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से उपस्थित है। उन्होंने कहा कि यह अनूठा संयोजन एक स्पष्ट संदेश देता है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत में विश्वास करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने सेमीकॉन इंडिया में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि वे एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।

हाल ही में जारी इस वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर, भारत ने हर आशा, हर अनुमान और हर पूवार्नुमान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक निज स्वार्थ से प्रेरित चिंताओं और चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वहीं भारत ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि यह वृद्धि सभी क्षेत्रों—विनिर्माण, सेवा, कृषि और निर्माण—में दिखाई दे रही है और हर क्षेत्र में उत्साह साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत का त्वरित विकास सभी उद्योगों और प्रत्येक नागरिक में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की यह गति भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर कर रही है।

सेमीकंडक्टर की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि 'तेल काला सोना था, लेकिन चिप डिजिटल हीरे हैं', इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल ने पिछली सदी को आकार दिया और दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव इस बात पर निर्भर करता था कि इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकाला गया। हालांकि, 21वीं सदी की शक्ति अब छोटी चिप में केंद्रित है। आकार में छोटे होने के बावजूद, ये चिप वैश्विक प्रगति को तेजी से बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार पहले ही 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वाले वर्षों में इसके 1 ट्रिलियन डॉलर को पार करने की आशा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिस गति से भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस 1 ट्रिलियन डॉलर के बाजार में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी।

भारत की त्वरित गति से प्रगति का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने याद दिलाया कि वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 तक, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्वीकृत हो चुका है। वर्ष 2024 में कई और संयंत्रों को स्वीकृति मिल गई है और वर्ष 2025 में पांच अतिरिक्त परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं वर्तमान में जारी हैं, जिनमें अठारह अरब डॉलर से अधिक यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश शामिल है। प्रधानमंत्री ने बल देते कहा कि यह भारत में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दशार्ता है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गति के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि फाइल से फैक्टरी तक का समय जितना कम होगा और कागजी प्रक्रिया जितनी कम होंगी, वेफर का काम उतनी ही जल्दी शुरू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों से सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर प्राप्त की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, निवेशकों को लंबी कागजी प्रक्रिया से मुक्ति मिल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत सेमीकंडक्टर पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जो भूमि, बिजली आपूर्ति, बंदरगाह और हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी और कुशल श्रमिकों के एक समूह तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहनों के साथ जोड़ा जाता है, तो औद्योगिक विकास अवश्यंभावी है। चाहे पीएलआई प्रोत्साहनों के माध्यम से हो या डिजाइन लिंक्ड अनुदानों के माध्यम से, भारत शुरूआत से अंत तक क्षमताएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि निवेश का प्रवाह जारी है। भारत बैकएंड ऑपरेशन से आगे बढ़कर एक पूर्ण-स्टेक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर के दृष्टिकोण पर विचार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने दोहराया कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव की आधारशिला रखेगी। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा देर से शुरू हुई, लेकिन अब हमें कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि सीजी पावर के पायलट प्लांट ने 28 अगस्त को, यानी सिर्फ. 4-5 दिन पहले, परिचालन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि केनेस का पायलट प्लांट भी जल्द ही शुरू होने वाला है। माइक्रोन और टाटा के परीक्षण चिप पहले से ही उत्पादन में हैं। उन्होंने दोहराया कि इस वर्ष वाणिज्यिक चिप उत्पादन शुरू हो जाएगा, जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति को दशार्ता है।

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, लखनऊ-कानपुर में दस-दस मार्गों पर चलेंगी निजी ई-बसें

(जीएनएस)।

लखनऊ। कानपुर और लखनऊ के दस-दस मार्गों पर निजी ई-बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। दोनों ही शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-बसों का संचालन नेट कास्ट कांट्रैक्ट (एनसीसी) माडल पर होगा। कुल 12 साल के लिए ई-बस चलाने का लाइसेंस दिया जाएगा।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि नेट कास्ट कांट्रैक्ट माडल में सरकार निजी संचालकों को ई-बस सेवा चलाने का लाइसेंस देगी। संचालन का मार्ग सरकार तय करेगी। किराया लखनऊ व कानपुर में चल रही सिटी बसों के लिए तय दर के अनुसार होगा। चार्जिंग के लिए सभी व्यवस्था निजी संचालक को करनी होगी।

बसों की पार्किंग व चार्जिंग का स्थान सरकार दी। चार्जिंग पाइंट पर बिजली कनेक्शन की व्यवस्था सरकार करेगी। ड्राइवर, कंडक्टर निजी संचालक को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मार्ग पर 10-10 ई-बसे चलाने का प्रस्ताव है। शुरूआत एक-एक बस से होगी। इसके बाद बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कुल 200 बसें चलाने का प्रस्ताव इन मार्गों पर हैं।

ई-बस संचालन में 10.30 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा। इसमें बसों की खरीद पर लगभग 9.50 करोड़ रुपये और चार्जर-उपकरण पर 80 लाख रुपये का खर्च संभावित है। संचालक को नौ मीटर की बस उपलब्ध करानी होगी ।जिसमें 28 बैठने की सीटें व 13 यात्रियों को खड़ा करके ले जाने की क्षमता होगी।

मंत्री ने बताया कि एक मार्ग पर एक ही निजी संचालक बस चलाएगा। अनुबंध होने के 90 दिन के अंदर संचालक को ई-बस का प्रोटोटाइप देना होगा। सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद ई-बसों की आपूर्ति होगी। एक साल के अंदर बस का संचालन शुरू करना होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगरीय परिवहन निदेशालय प्रदेश के 15 नगर निगमों में 743 ई-बसों का संचालन करता है। इसमें 700 बसों का संचालन निदेशालय ग्रास कास्ट कांट्रैक्ट (जीसीसी) मोड में कर रही है। इसमें केंद्र सरकार ने निजी संचालकों को छूट की व्यवस्था की थी।

लखनऊ में इन मार्गों पर चलेंगी ई-बसें

चारबाग से बाराबंकी, चारबाग से देवा, चारबाग से कुर्सी, कमता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराज खंड, घंटाघर से माल थाना, घंटाघर से संडीला, स्कूटर इंडिया से इंजीनियरिंग कालेज, दुबग्गा से गंगागंज

कानपुर के इन मार्गों पर चलेंगी बसें

घंटाघर से अकबरपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिंदकी, कानपुर रेलवे स्टेशन से बिठूर, कानपुर रेलवे स्टेशन से घाटमपुर, कानपुर रेलवे स्टेशन से आईआईटी, घंटाघर से मूसानगर, कानपुर सिटी सर्कुलर रोड, रामा देवी से जहानाबाद, फजलगंज से रूरा, कानपुर रेलवे स्टेशन से उन्नाव।

बागेश्वर महाराज के बयान का सन्तों ने किया समर्थन : बृजभूमि में मांस, मदिरा नहीं बिकना चाहिए

मथुरा (जीएनएस)। बृजभूमि के सभी सन्तो ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। जानकारी के अनुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि ब्रजभूमि में दूध, दही, छाछ का सेवन होना चाहिए। कहा कि यहां पर मांस, मदिरा नहीं बिकना चाहिए। यह गोलोक भूमि है, यहां भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया है। वहीं महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने भी कहा कि ब्रजभूमि में

मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए तथा इनकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी के साथ अंकित कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जहां पर बृजवासी प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं, वहां पर मांस मदिरा भी बिक रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीक्रम में महामंडलेश्वर राधानंद गिरी ने कहा कि जहां पर हमारे कान्हा ने रासलीला की है, वहां पर मांस और शराब नहीं बिकनी चाहिए। इसी के साथ प्रिया किशोरी ने भी बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री की बयान का समर्थन किया है।

बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने निःशुल्क बस यात्रा की सरकार से की मांग

लखनऊ रीडर

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में आगामी 6 और 7 सितंबर को यूपीएसएसएससी पेट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने सरकार से निःशुल्क बस यात्रा की मांग की है।

बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय द्वारा मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ सिंह को भेज गए पत्र यह परीक्षा प्रदेश के 48 जिलों में चार पालियों में कराई जाएगी, इसमें लाखों की संख्या में युवा अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, इस कारण गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं को गंभीर आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रोडवेज बसों में पेट परीक्षा अभ्यर्थियों के निःशुल्क यात्रा सुविधा की सरकार से मांग की है। उनका कहना हैकि यदि सरकार यह सुविधा देती है तो लाखों युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी और वे परीक्षा पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। गौरतलब है कि हर साल होने वाली इस परीक्षा में प्रदेश के कोने-कोने से युवा भाग लेते हैं और यात्रा व्यय की समस्या उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। ऐसे में यदि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है तो यह युवाओं के हित में ऐतिहासिक पहल होगी।

थल सेना से सेवानिवृत सूबेदार पंकज दत्त कौशिक का नूरपुर में हुआ भव्य स्वागत

लखनऊ रीडर / शारिक जैदी

बिजनौर। नूरपुर कस्बे के मोहल्ला गोविंद नगर निवासी सूबेदार पंकज दत्त कौशिक मंगलवार को थल सेना से सेवानिवृत होकर अपने गृह नगर पहुंचे। परिजनों और शुभचिंतकों ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया।

पंकज दत्त कौशिक अगस्त 1995 में सेना में भर्ती हुए थे और अगस्त 2025 में उन्होंने सेवानिवृत्ति प्राप्त की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में सेवाएं दीं और कई अहम सैन्य अभियानों में भाग लिया।

सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्होंने कहा कि थल सेना ने हमेशा दुश्मनों को करारा जवाब देकर इतिहास रचा है। यह सेवा मेरे जीवन का स्वर्णिम अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें।

उनके स्वागत समारोह में

परिवारजन, रिश्तेदार, राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र की कई हस्तियां और सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगमों में 12 घंटे का विशेष अभियान

(जीएनएस)।

लखनऊ, दो सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों में स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं और जन-जागरुकता के लिए 12 घंटे का विशेष अभियान चलाया गया। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

बयान के अनुसार यह पहल स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों के अनुरूप स्थानीय समस्याओं का समाधान करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई। यह अभियान न केवल लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में सफल रहा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी मजबूत करता है।

बयान के अनुसार लखनऊ नगर निगम ने सभी आठ जोनों में 32 कर वसूली और शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में 1,365 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया और एक दिन में 2.30 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ। गोरखपुर नगर निगम ने दुकानदारों को कपड़े के थैले वितरित किए। इसके अलावा एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुमार्ना भी लगाया गया।

जमुनापार पुलिस ने पकड़ा वांछित : अवैध हथियार बरामद

मथुरा (जीएनएस)। थाना जमुनापार क्षेत्र स्थित डहरूआ फाटक के पास से पुलिस ने एक वांछित को अवैध हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी जमुनापार विदेश कुमार पुलिस टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में जुटे हुए थे। उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर उन्होंने डहरूआ फाटक के पास से वांछित आरोपी नरेन्द्र चौधरी पुत्र रनवीर सिंह निवासी सिद्धार्थनगर कॉलोनी थाना जमुनापार को घेरकर दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया

मुख्यमंत्री और एसडीएम से शिकायत पेड़ काट डालने की शिकायत

लखनऊ रीडर

फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के बसावन का पुरवा मजरे बैगांव निवासी ग्रामीणों ने फलदार हरे पेड़ काट डालने की मुख्यमंत्री जनसुनवाई और खागा एसडीएम से शिकायत की है।

गांव के सोहनलाल, जयसिंह, रामनरेश गंगाराम, छोटेलाल ने शिकायती पत्र में बताया कि गांव में उनकी पुश्तैनी बाग है। उसमें आम, आंवला, इमारती लकड़ी तथा कई अन्य फलदार हरे वृक्ष खड़े थे। उक्त बाग के कुछ हरे फलदार पेड़ों को गांव के दबंगों ने काट डाला। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने कटान कर रहे दबंगों को रोक दिया। ग्रामीणों ने दबंगों के कार्यवाही की मांग की है। एसडीएम अभिनीत कुमार ने जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है।

आईसीएफए और बीएल एग्रो ने उत्तर प्रदेश में कृषि के भविष्य को आकार देने के लिए हाथ मिलाया

बीएल एग्रो के चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल यूपीएसएससी चेयरमैन के रूप में उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के नए युग की अगुवाई करेंगे

लखनऊ, 2 सितंबर, 2025- इंडियन चैंबर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर (आईसीएफए) ने मंगलवार को लखनऊ के रेनेसां होटल में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि परिषद (यूपीएसएसी) का सफलतापूर्वक पुनर्गठन किया। यह परिषद नीतिगत वकालत, कृषि व्यवसाय विकास, कारोबारी सुगमता और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य के शीर्ष मंच के रूप में कार्य करेगी।

इस अवसर पर, बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल को औपचारिक रूप से यूपीएसएसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके साथ सीपीसीएआर के महानिदेशक डॉ. संजय सिंह को-चेयरमैन और डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (ईडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री रोशन लाल तमक वाइस-चेयरमैन के रूप में उपस्थित रहे।इस शुभारंभ के साथ ही निवेश और कृषि निर्यात पर एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसका विषय था "उत्तर प्रदेश में कृषि का भविष्य गढ़ना"। इसमें सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के 70-100 से ज्यादा वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिनमें नाबार्ड, कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, इन्वेस्ट यूपी, मंडी परिषद के सीईओ, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और कृषि-व्यवसाय के प्रमुख अधिकारी शामिल थे।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) श्री दिनेश सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की कृषि रीढ़ को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और अगर किसानों और उद्योगों को एक स्पष्ट

रोडमैप दिया जाए, तो वे निस्संदेह राज्य को, खासकर निर्यात क्षेत्र में तेजी से विकास की ओर ले जाएंगे। मैं आईसीएफए से आग्रह करता हूं कि वह स्थानीय स्तर पर ऐसे आयोजनों की पहल करे जो हमारे उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाएं और राज्य के कृषि-निर्यात परिदृश्य में सार्थक बदलाव लाएं।ह्वआईसीएफए के मानद चेयरमैन डॉ. एम.जे. खान ने उत्पादन से हटकर व्यापार की ओर बढ़ने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश उत्पादन तो बहुत करता है, लेकिन व्यापार बहुत कम करता है। अगर हमें अपने किसानों को सचमुच सशक्त बनाना है, तो इस असंतुलन को दूर करना होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकियां अब हमें इस अंतर को पाटने और अपनी उपज को बाजारों से कुशलतापूर्वक जोड़ने का अवसर प्रदान करती हैं। एक अन्य प्राथमिकता बागवानी होनी चाहिए, जहां हमारा हिस्सा अभी भी बहुत कम है। बीज उत्पादन जैसे उप-क्षेत्रों पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं।"

अपने मुख्य भाषण में, श्री घनश्याम खंडेलवाल ने इस दिन को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा, "आज, हमने उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण देखा है। यूपीएसएसी का यह पुनर्गठन, निवेश और कृषि निर्यात पर गोलमेज सम्मेलन के साथ एक नए युग की शुरूआत का संकेत देता है। जहां उत्तर प्रदेश हमेशा उत्पादन में अग्रणी रहा है, वहीं अब हमें प्रसंस्करण और निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इससे हमारी कृषि अधिक प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त होगी। हमारा रोडमैप मूल्य संवर्धन को प्राथमिकता देगा, जिससे कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान दोगुना हो जाएगा।"आईसीएफए के निदेशक श्री तुषार शर्मा ने घोषणा की कि आईसीएफए की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कृषि-प्रदर्शनी, एग्रोवर्ल्ड 2025 पहली बार लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यह पारंपरिक रूप से नई दिल्ली में आयोजित होती है।

उन्होंने कहा, "यह उत्तर प्रदेश को दुनिया से और दुनिया को उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा।"

श्री शर्मा ने अंत में कहा, "भारत का कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश, कृषि-आधारित उद्योगों और निर्यात के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। खाद्यान्न, गन्ना, फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते, यह राज्य खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, वेयरहाउसिंग और कृषि-प्रौद्योगिकी नवाचारों में निवेश के अपार अवसर प्रदान करता है।"

उत्तर प्रदेश में निवेश और कृषि निर्यात के अवसरों पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन के दौरान, लीड्सकनेक्ट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और बीएल एग्रो के सीईओ श्री

नवनीत रविकर ने कहा, "उत्तर प्रदेश कृषि-आधारित विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और बीएल एग्रो गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी और मजबूत मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता को प्रीमियम निर्यात में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सभा को संबोधित करते हुए यूपीएसएसी के मानद चेयरमैन श्री मुकेश सिंह ने परिषद की विविधता और समावेशिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "इस पुनर्गठित परिषद का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की उपस्थिति है, जो हमारे विचार-विमर्श में अत्यंत आवश्यक विविधता ला रही है। यह विविधता उत्तर प्रदेश में कृषि के भविष्य की योजना बनाते समय संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगी। मैं आज सभी गणमान्य व्यक्तियों, सदस्यों और प्रतिनिधियों के योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सत्र को उत्पादक और ऐतिहासिक बनाया है।"

शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे नेताओं को पुलिस ने रोका तो बैठे धरने पर -लगाए सरकार विरोधी नारे

लखनऊ रीडर

धाता। अजरौली कांड को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे आप नेताओं को पुलिस ने रोक लिया, इससे नाराज होकर वह सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारे लगाए।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीराम पटेल की अगुवाई में मंगलवार को कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। जैसे वह धाता तिराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। उनका कहना रहा कि

अब शोक संवेदना में भी रोक लगने लगी। उन्होंने आम जनता की आवाज दबाने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस पर तानाशाही रवैया का आरोप लगाया। मजबूरन उन्हें शाम को वापस लौटना पड़ा। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो पार्टी द्वारा व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार, व्यापार प्रकोष्ठ फतेहपुर के जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह, महिला प्रकोष्ठ की जिला उपाध्यक्ष माया गौतम, विधानसभा खागा के पूर्व प्रत्याशी विजय गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष मुहम्मद शाहजहां, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र मौर्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विभिन्न जिलों आए उलेमा-ए-इकराम के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री अखिलेश यादव से सपा प्रदेश मुख्यालय में मुलाकात की

लखनऊ , समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जिलों आए उलेमा-ए-इकराम के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उलेमा-ए-इकराम ने श्री अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की दुआ की।

इस अवसर पर उलमा-ए-इकराम में एक स्वर में श्री अखिलेश यादव के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा कि हम यकीन से यह बात कहते है कि आप नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चल रहे है। हम सभी लोग पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी के साथ है। श्री अखिलेश यादव ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का सभी से एक भावनात्मक रिश्ता है। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा हो गयी है। कानून का राज नहीं रह गया है। निदोर्षों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग में हत्याएं हो रही है। पुलिस हिरासत में मौतें हो रही है। भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस का गैरकानूनी इस्तेमाल कर रही है। भाजपा प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार, लूट बेईमानी चरम पर है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में बर्बाद कर दिया हैं आज किसानों, नौजवानों छात्रों

समेत सभी वर्गों की कोई सुनवाई नहीं हैं। भाजपा सरकार ने बुनकरों का कारोबार चौपट कर दिया है। भाजपा नफरत का कारोबार करती है।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कमजोर करने में समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। भाजपा को सत्ता से बाहर करना ही देश हित में है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। पीडीए की नीति पर चलकर सबके कल्याण, विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सबके साथ इंसाफ होगा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र, संविधान और वोट का अधिकार बचाने के लिए भाजपा से सावधान रहना होगा। भाजपा नफरत और साम्प्रदायिकता की राजनीति करती है। भाजपा चुनाव में हर स्तर पर बेईमानी करती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं को सतर्क रहना होगा। बूथ को और मजबूत करना होगा। कार्यकताओं का काम बहुत बढ़ गया है। वोट बनवाना, वोट बचाना, वोट पड़वाना और वोट गिनवाना। हर काम को पूरी मेहनत और जागरूकता से करना होगा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार विदेश नीति से लेकर हर मोर्चे पर फेल है। चीन भारत का दोस्त नहीं हो सकता है। चीन हमारे कारोबार और व्यापार पर कब्जा कर रहा है। चीन पर भारत की निर्भरता ठीक नहीं है।

समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मो0 शकील नदवी के साथ आज श्री अखिलेश यादव से भेंटकताओं में प्रमुख थे सर्वश्री मौलाना आरिफ (जहूर कासमी), राव कारी सलीम देवबंद, मौलाना अब्दुल हलीम साहब, मौलाना अशरफ साहब, मौलाना इकबाल साहब, मौलाना सुफियान साहब, मौलाना शमशाद साहब, मौलाना उमैर साहब, मुफ्ती मोहम्मद मुदस्सिर साहब, बहरोज आलम (जहूर कासमी), कारी मो. असगर साहब, कारी अफजाल साहब, सूफी मुकीम साहब जगेता, कारी जुनैद साहब, कारी सईद अहमद, साहब, मुफ्ती साबिर साहब, मुफ्ती अतहर साहब, हाजी अय्यूब साहब, मौलाना हारुन साहब, मौलाना रेहान साहब, मुफ्ती जुल्फिकार साहब, मौलाना आकिल साहब, मौलाना रिजवान साहब, मुफ्ती नुवेद साहब, कारी सुएब साहब, कारी नईम साहब, कारी इमरान साहब, मौलाना फरमान साहब, मौलाना आलिशान साहब आदि।

इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री किरनमय नंदा, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी, राष्ट्रीय सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्री श्याम लाल पाल तथा श्री तेजंदर विर्क की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।